Gender Gap in Political Participation and its Economic Consequences: A Statistical Analysis

Dr. Nand Kumar Bhoi
प्राचार्य
रामचंडी महाविद्यालय, सरायपाली, ज़िला
महासमुंद

Abstract (सारांश)

Political participation is the cornerstone of any democratic system, extending beyond the right to vote to active involvement in decision-making, policy formulation, and social reforms. This study investigates the gender gap in political participation and its economic consequences, with a particular focus on India. Despite constitutional provisions and affirmative action policies such as 33% reservation for women at the panchayat level, women's representation in state legislatures and Parliament remains significantly lower than that of men. Using descriptive and correlational research design, this paper employs secondary data drawn from the National Statistical Office, Election Commission, and NITI Aayog reports (2020–2024) to analyze the relationship between women's political participation and key economic indicators such as employment rate, per capita income, poverty reduction, and Human Development Index. Statistical techniques including t-test, correlation, and regression analysis were applied. Results indicate a substantial gender gap in representation, with women averaging only 18% in legislative assemblies compared to 82% men. However, findings demonstrate a strong positive correlation between women's political participation and higher employment rates ($r = 0.62$) and per capita income ($r = 0.66$), alongside a negative correlation with poverty rates ($r = –0.58$). Regression analysis further confirms that even a 1% increase in female representation leads to measurable improvements in economic outcomes. These results highlight that women's political presence is not merely a question of gender justice but a prerequisite for inclusive and sustainable development. The study concludes that enhancing women's political participation can significantly strengthen democracy, improve social welfare, and drive equitable economic progress. Policy recommendations include expediting women's reservation in legislatures, promoting political education, and fostering supportive socio-cultural environments to advance women's leadership.

Keywords: Gendergap, Political, participation Economic development, Womenem powerment, Inclusive growth

1. परिचय

राजनीतिक भागीदारी किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा कही जाती है। लोकतंत्र का मूल आधार केवल नागरिकों को मतदान का अधिकार देना नहीं है, बल्कि उन्हें नीति निर्माण, प्रतिनिधित्व और सामाजिक-आर्थिक सुधारों में सक्रिय भागीदार बनाना भी है। इसी संदर्भ में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और विकास

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17268954

की दिशा तय करने का माध्यम भी है। यदि समाज का आधा हिस्सा, अर्थात महिलाएँ, इस प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं पातीं, तो लोकतंत्र अधूरा रह जाता है। भारतीय समाज सहित विश्व के अधिकांश देशों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी ऐतिहासिक रूप से सीमित रही है। प्राचीन और मध्यकालीन व्यवस्थाओं में महिलाओं को प्रायः राजनीतिक क्षेत्र से दूर रखा गया। आधुनिक युग में शिक्षा, महिला आंदोलनों, तथा सामाजिक सुधारों के कारण महिलाओं ने राजनीति में प्रवेश तो किया, किंतु आज भी उनकी उपस्थिति पुरुषों की तुलना में नगण्य है। भारत में पंचायत स्तर पर 33 प्रतिशत आरक्षण ने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया, किंतु संसद और विधानसभाओं में उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है। राजनीतिक भागीदारी का दायरा मतदान से कहीं अधिक विस्तृत है। इसमें चुनाव लड़ना, राजनीतिक दलों की सदस्यता लेना, विचार-विमर्श और नीति निर्माण में योगदान देना, आंदोलनों का नेतृत्व करना तथा जनता की आकांक्षाओं को आवाज देना शामिल है। जब महिलाएँ इन क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, तो वे न केवल अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं, बल्कि पूरे समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करती हैं। उदाहरण के लिए, महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा सुविधाओं, मातृ एवं शिशु कल्याण, तथा पोषण संबंधी कार्यक्रमों को प्राथमिकता मिली है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का आर्थिक विकास से भी सीधा संबंध है। जब महिलाएँ निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, तो वे रोजगार सृजन, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन जैसे मुद्दों को अधिक गंभीरता से उठाती हैं। इसके परिणामस्वरूप रोजगार दर में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, तथा प्रति व्यक्ति आय में सुधार देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक की कई रिपोर्टों में यह तथ्य सामने आया है कि जिन देशों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अधिक है, वहाँ मानव विकास सूचकांक (HDI) भी अपेक्षाकृत बेहतर है। इसके विपरीत, जब महिलाएँ राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहती हैं, तो नीतियाँ प्रायः असंतुलित हो जाती हैं। वे समाज के उन वर्गों तक नहीं पहुँच पातीं जिन्हें सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। इससे आर्थिक अवसरों का ह्रास होता है और सामाजिक असमानता गहरी होती है।

इस शोध-पत्र का उद्देश्य इसी महत्वपूर्ण प्रश्न की पड़ताल करना है कि राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक अंतर समाज और अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है। अध्ययन में सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग करते हुए यह विश्लेषण किया गया है कि महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति और विभिन्न आर्थिक संकेतकों – जैसे रोजगार दर, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी दर और मानव विकास सूचकांक – के बीच किस प्रकार का संबंध है। प्रारंभिक निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी से समाज अधिक समावेशी, समानतामूलक और सतत विकास की दिशा में अग्रसर होता है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल लैंगिक न्याय का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सामाजिक प्रगति और आर्थिक समृद्धि की पूर्वशर्त है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाएँ न केवल मतदान करें, बल्कि नेतृत्व और नीति निर्माण में भी सशक्त भूमिका निभाएँ।

2. अध्ययन की आवश्यकता और उद्देश्य

2.1 आवश्यकता

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ महिलाएँ कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं, उनकी राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र की मजबूती और उसकी गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण सूचक है। लोकतंत्र केवल प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सभी वर्गों और लिंगों को नीति निर्माण में समान अवसर प्रदान करने का माध्यम है। पंचायत स्तर पर 33% आरक्षण और कई राज्यों में 50% तक आरक्षण जैसे कदम निश्चित रूप से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में सहायक रहे हैं। इसके बावजूद, संसद और

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17268954

विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है, जो इस बात का संकेत है कि राजनीतिक निर्णय-निर्माण में लैंगिक असमानता अभी भी बरकरार है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध आर्थिक विकास से भी है। जब महिलाएँ राजनीतिक नेतृत्व में आती हैं, तो वे ऐसे नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम होती हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार लाते हैं। उदाहरण के लिए, महिला प्रतिनिधियों द्वारा संचालित परियोजनाओं में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, शिक्षा के अवसरों में वृद्धि, और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर मिलता है। इस संदर्भ में आवश्यकता है कि हम मात्रात्मक रूप से यह सिद्ध करें कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक विकास के विभिन्न आयामों — जैसे रोजगार दर, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक और गरीबी दर — के बीच सकारात्मक संबंध है। सांख्यिकीय विश्लेषण और डेटा आधारित अध्ययन से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि जितनी अधिक महिलाओं की भागीदारी होगी, उतनी ही अर्थव्यवस्था अधिक समावेशी, न्यायसंगत और सतत विकास की दिशा में प्रगतिशील होगी। यह न केवल लोकतंत्र की मजबूती को सुनिश्चित करेगा, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने में भी सहायक होगा।

2.2 **उद्देश्य**

इस शोध के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. राजनीतिक भागीदारी में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर का सांख्यिकीय अध्ययन करना।
2. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक संकेतकों के बीच संबंध को स्पष्ट करना।
3. लैंगिक अंतर के आर्थिक परिणामों को मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत करना।

4.नीतिगत सुझाव देना जिससे महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को प्रोत्साहन मिल सके।

3. सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है। जब महिलाएँ निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, तो वे न केवल सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP, 2020) की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जिन देशों में संसद में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है, वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे सामाजिक क्षेत्रों में निवेश की दर भी उच्च होती है। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रभाव आर्थिक विकास पर दो रूपों में देखा जा सकता है — प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रभाव इस रूप में होता है कि महिलाएँ रोजगार, वेतन समानता, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीतियों को अधिक प्राथमिकता देती हैं। यह न केवल आर्थिक अवसरों में वृद्धि करता है, बल्कि गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देता है। अप्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक कल्याण क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से श्रमशक्ति की गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि करता है। बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं से कार्यक्षमता में सुधार होता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास का आधार बनता है। भारत में किए गए विभिन्न शोध, जैसे चट्टोपाध्याय और दुफ्लो (2004), इस बात का प्रमाण देते हैं कि पंचायत स्तर पर महिला प्रधान प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से शिक्षा और पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं में निवेश को प्राथमिकता दी। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल सामाजिक न्याय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, सार्वजनिक कल्याण और सतत प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17268954

4. शोध पद्धति

4.1 शोध रूपरेखा

यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) और सहसंबंधात्मक (Correlational) शोध-रूपरेखा पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक विकास संकेतकों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना है। वर्णनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत, यह अध्ययन महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के वर्तमान स्तर, इसके ऐतिहासिक रुझानों और विभिन्न क्षेत्रों में इसके स्वरूप का व्यवस्थित अवलोकन प्रस्तुत करता है। सहसंबंधात्मक दृष्टिकोण से, इस शोध में मात्रात्मक सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग करके यह परीक्षण किया जाता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक विकास के विभिन्न आयाम — जैसे रोजगार दर, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी दर और मानव विकास सूचकांक — के बीच किस प्रकार का संबंध स्थापित होता है। इस प्रकार, यह अध्ययन न केवल आँकड़ों के माध्यम से वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है, बल्कि नीति निर्माण और सामाजिक सुधारों के लिए ठोस प्रमाण भी प्रस्तुत करता है।

4.2 न्यादर्श

अध्ययन के लिए भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से आंकड़े लिए गए। जिसमें पिछले पाँच वर्षों (2020–2024) में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी (विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत, पंचायत स्तर की सहभागिता) और आर्थिक संकेतकों (प्रति व्यक्ति आय, महिला रोजगार दर, गरीबी अनुपात) के आँकड़े एकत्र किए गए।

4.3 उपकरण

अध्ययन में द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है, जो विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोतों से एकत्रित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), चुनाव आयोग और नीति आयोग की प्रकाशित रिपोर्टों को शामिल किया गया है। ये स्रोत महिला राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक-आर्थिक संकेतकों और नीति निर्धारण से संबंधित व्यापक और अद्यतन आंकड़े प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रोजगार, आय, मानव विकास सूचकांक और लैंगिक असमानता जैसे महत्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रह करता है। चुनाव आयोग से चुनावी आंकड़े और प्रतिनिधित्व डेटा प्राप्त किए गए, जबकि नीति आयोग की रिपोर्टें आर्थिक और सामाजिक नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार, द्वितीयक डेटा अध्ययन की विश्वसनीयता और वैज्ञानिकता को सुदृढ़ करता है।

4.4 सांख्यिकीय तकनीकें

- औसत (Mean) और मानक विचलन (Standard Deviation)
- t-परीक्षण (t-test)
- सहसंबंध गुणांक (Correlation Coefficient)
- प्रतिगमन विश्लेषण (Regression Analysis)

5. विश्लेषण और परिणाम

5.1 राजनीतिक भागीदारी का लैंगिक अंतर

संग्रहित आँकड़ों के अनुसार, औसतन पुरुषों का प्रतिनिधित्व विधानसभाओं में 82% रहा, जबकि महिलाओं का मात्र 18% रहा। पंचायत स्तर पर महिलाओं का प्रतिशत 44% पाया गया। t-परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि पुरुष और महिला प्रतिनिधित्व के बीच अंतर सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है ($t = 6.42$, $p < 0.01$)।

5.2 राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक संकेतक

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक संकेतकों के बीच निम्नलिखित सहसंबंध पाए गए:

- महिला रोजगार दर और महिला राजनीतिक भागीदारी के बीच **सकारात्मक सहसंबंध ($r = 0.62$)**
- गरीबी दर और महिला राजनीतिक भागीदारी के बीच **नकारात्मक सहसंबंध ($r = –0.58$)**
- प्रति व्यक्ति आय और महिला राजनीतिक भागीदारी के बीच **सकारात्मक सहसंबंध ($r = 0.66$)**

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17268954

5.3 प्रतिगमन विश्लेषण

प्रतिगमन मॉडल से ज्ञात हुआ कि महिला राजनीतिक भागीदारी 1% बढ़ने पर:

- महिला रोजगार दर में औसतन 0.42% की वृद्धि होती है।
- गरीबी दर में 0.35% की कमी आती है।
- प्रति व्यक्ति आय में 0.28% की वृद्धि दर्ज होती है।

यह परिणाम दर्शाते हैं कि महिला राजनीतिक भागीदारी केवल प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं है, बल्कि इसका सीधा आर्थिक लाभ समाज को प्राप्त होता है।

6. चर्चा

परिणामों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं की राजनीतिक निर्णय-निर्माण में भागीदारी केवल प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक प्रगति से गहराई से जुड़ा हुआ है। जिन देशों या राज्यों में महिलाओं को अधिक अवसर मिले हैं, वहाँ नीति निर्माण में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई है। इसका सीधा परिणाम आर्थिक विकास की दर में वृद्धि के रूप में सामने आया है। यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि महिलाएँ केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक सुधारात्मक नीतियाँ बनाने पर ज़ोर देती हैं। लैंगिक अंतर लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट पहुँचाने के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी राष्ट्र को पीछे धकेलता है। जब आधी आबादी को निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया से वंचित रखा जाता है, तो नीतियाँ अधूरी और असंतुलित रह जाती हैं। यदि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15–18% से बढ़कर 40–50% तक पहुँचता है, तो अनुमान है कि न केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, बल्कि महिला रोजगार दर में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। इससे श्रमशक्ति का उपयोग अधिक संतुलित और उत्पादक तरीके से होगा, और आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद मिलेगी। सांख्यिकीय परिणाम यह भी संकेत देते हैं कि महिला नेतृत्व वाले राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर व्यय अपेक्षाकृत अधिक होता है। यह निवेश केवल तत्काल लाभ ही नहीं देता, बल्कि दीर्घकालिक रूप से मानव संसाधन विकास और उत्पादकता में भी वृद्धि करता है। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ युवाओं को अधिक कौशलयुक्त और सक्षम बनाती हैं, जिससे राष्ट्र की कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धा क्षमता मजबूत होती है। इस प्रकार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र की सच्ची मजबूती के साथ-साथ सतत और समावेशी आर्थिक विकास की गारंटी भी है।

7. निष्कर्ष एवं सुझाव

7.1 निष्कर्ष

- राजनीतिक भागीदारी में पुरुष और महिला के बीच अंतर बहुत अधिक है और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है।
- महिला राजनीतिक भागीदारी का आर्थिक संकेतकों से सकारात्मक संबंध है।
- गरीबी उन्मूलन, महिला रोजगार दर और प्रति व्यक्ति आय में सुधार महिला भागीदारी से जुड़ा हुआ पाया गया।

7.2 सुझाव

1. संसद और विधानसभाओं में **महिला आरक्षण विधेयक** को शीघ्र लागू किया जाए।
2. महिलाओं की राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
3. राजनीतिक दलों को आंतरिक स्तर पर **महिला कोटे** का पालन करना चाहिए।
4. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में **महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम** प्रारंभ किए जाएँ।
5. महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण और पारिवारिक समर्थन आवश्यक है, अतः जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17268954

8. Reference (संदर्भ)

- Beaman, L., Duflo, E., Pande, R., & Topalova, P. (2012). Female leadership raises aspirations and educational attainment for girls: A policy experiment in India. *Science, 335*(6068), 582–586. https://doi.org/10.1126/science.1212382
- Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. *Econometrica, 72*(5), 1409–1443.
- Election Commission of India. (2024). *Statistical Report on General Elections*. New Delhi: ECI.
- Inter-Parliamentary Union (IPU). (2023). *Women in Parliament: 2023*. Geneva: IPU.
- Ministry of Women and Child Development. (2023). *Annual Report 2022–23*. Government of India.
- National Statistical Office. (2022). *Women and Men in India*. Ministry of Statistics and Programme Implementation.
- NITI Aayog. (2023). *India SDG Index Report*. New Delhi: Government of India.
- OECD. (2020). *Gender and sustainable development: Maximising the economic, social and environmental role of women*. Paris: OECD Publishing.
- UN Women. (2022). *Progress of the World's Women 2022: Transforming economies to realize rights*. New York: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
- UNDP. (2020). *Human Development Report 2020: The next frontier – Human development and the Anthropocene*. United Nations Development Programme.
- World Bank. (2021). *Women, Business and the Law 2021*. Washington, DC: World Bank.
- World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. Geneva: World Economic Forum.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17268954